2 सुशासन ने मुख्यमंत्री साय को दिलाया ऊँचा स्थान

3 सरिता संदीप जैन पालिका अध्यक्ष

5 सोमदत्त शास्त्रीः व्यवहार में सरल, सहज, आत्मीय

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 17 प्रति सोमवार, 1 सितंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की करतूत से धूमिल हुई भाजपा की छवि, कलेक्टर पर उठाया हाथ

कुशवाहा के इस कृत्य पर लीपापोती प्रशासनिक गरिमा की रक्षा का मामला नहीं, बल्कि पार्टी की छवि बचाने की भी अंतिम कसौटी

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

भारतीय जनता पार्टी की पहचान हमेशा से सुशासन, अनुशासन और सेवा के नारों से जुड़ी रही है, लेकिन जब पार्टी के ही जनप्रतिनिधि इन मूल्यों को ठेस पहुँचाते हैं, तो उसकी साख पर गहरा दाग लगता है। ताजा मामला भिंड का है, जहां भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ अभद्रता करते हुए हाथ उठा दिया। यह घटना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान है बल्कि भाजपा की उस छवि को भी धूमिल करती है, जिसे वर्षों की मेहनत से गढ़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी बार-बार सुशासन और अनुशासन की राजनीति को जनता के सामने प्रस्तुत करती रही है। परंतु जब उसके अपने विधायक ही सुशासन के प्रतीक माने जाने वाले कलेक्टर पर हाथ उठाने से नहीं चूकते, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर अनुशासन का पालन कौन कराएगा। विधायक का यह कृत्य लोकतांत्रिक मर्यादा और प्रशासनिक गरिमा की खुली अवहेलना है, जिसे किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं ठहराया जा सकता।

प्रशासन पर सीधा हमला

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जिले की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख अधिकारी हैं। उन पर हाथ उठाना दरअसल पूरे प्रशासनिक तंत्र को चुनौती देने जैसा है। विधायक का यह व्यवहार जिले में काम कर रहे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला है। यह संदेश जाता है कि यदि विधायक ही प्रशासनिक अधिकारियों को अपमानित करेंगे, तो आम जनता का विश्वास शासन-प्रशासन पर कैसे कायम रहेगा।

(शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में निवेश का नया द्वार खोलने विदेश यात्रा पर गए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जापान और दक्षिण कोरिया से लौटे, औद्योगिक नीति पर निवेशकों से की चर्चा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में विदेशी निवेश लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हाल ही में दस दिवसीय जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पूरी की। मुख्यमंत्री 30 अगस्त को रायपुर लौट आए। इस यात्रा को प्रदेश की औद्योगिक नीति और भविष्य की आर्थिक प्रगति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जापान और दक्षिण कोरिया के विभिन्न औद्योगिक शहरों, निवेशक समूहों और कंपनियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न राज्य बताते हुए निवेशकों को यहां की भू-संपदा, जल-संपदा, वन-संपदा और खनिज-संपदा से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ न केवल खनिजों का भंडार है, बल्कि यहां की भूमि और जल संसाधन भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक और कृषि निवेश के लिए अनुकूल है।

औद्योगिक नीति 2024-30 पर प्रस्तुत की दृष्टि

विदेशी निवेशकों के साथ हुई बैठकों में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने निवेशकों को बताया कि यह नीति पारदर्शिता, सुगमता और स्थायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। नई इकाइयों को भूमि आवंटन की सरल प्रक्रिया। बिजली, पानी और परिवहन में रियायतें। पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहन। स्टार्टअप और नवाचार को विशेष सहायता। साय ने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता केवल उद्योगों की स्थापना नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार सृजन है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर स्तर पर उनकी सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करेगी।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान यह स्पष्ट किया कि विदेशी निवेश का सबसे बड़ा उद्देश्य छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुशल और अर्द्धकुशल युवाओं की बड़ी आबादी है, जिन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर मिलते ही वे विश्व स्तरीय उत्पादन क्षमता का परिचय दे सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को उद्योगों से जोड़ने की योजना बनाई है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में निवेश का नया द्वार खोलने विदेश यात्रा पर गए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

(पेज 1 का शेष)

जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा इसलिए आवश्यक

मुख्यमंत्री की यात्रा में जापान और दक्षिण कोरिया का चयन रणनीतिक दृष्टि से किया गया। जापान तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में दुनिया का अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने वहां की कंपनियों से हाई-टेक विनिर्माण इकाइयों को छत्तीसगढ़ में लगाने का आग्रह किया। दक्षिण कोरिया स्टील, शिप बिल्डिंग और आईटी क्षेत्र का दिग्गज है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को देखते हुए कोरियाई कंपनियों के साथ साझेदारी को बेहद संभावनाशील माना जा रहा है। दोनों देशों ने छत्तीसगढ़ के प्रस्तावों में गहरी रुचि दिखाई और संभावित निवेश की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया।

पर्यावरण और स्थायी विकास पर बल

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि हरित उद्योगों और नवीकरणीय ऊर्जा को भी प्राथमिकता दे रहा है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा और बायोमास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निवेश तभी स्वागत योग्य है जब वह पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों का सम्मान करे।

लौटने पर मुख्यमंत्री का संदेश

रायपुर लौटने पर मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से बातचीत में कहा "यह यात्रा छत्तीसगढ़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। हमने जापान और दक्षिण कोरिया के उद्योगपतियों के साथ उपयोगी चर्चा की। उन्होंने हमारे राज्य की नई औद्योगिक नीति और संसाधनों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आएगा और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।"

विपक्ष और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने जहां इस यात्रा को महज दिखावा बताया, वहीं आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को सक्रिय पहल करनी ही होगी। छत्तीसगढ़ जैसी खनिज और प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न भूमि यदि सही नीतियों के तहत उपयोग में लाई जाती है, तो यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे देश की आर्थिक वृद्धि को गति दे सकती है।

मुख्यमंत्री की नजर में छग का भविष्य

यह यात्रा छत्तीसगढ़ को निवेश मानचित्र पर अधिक सशक्त बनाने का प्रयास है। आने वाले समय में यदि विदेशी निवेशकों के साथ हुए समझौते मूर्त रूप लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उद्योगों के साथ-साथ सहायक क्षेत्रों में भी प्रगति होगी। राज्य की आय और जीडीपी में वृद्धि होगी। युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की ठोस तैयारी है। उनकी कोशिश है कि प्रदेश की पहचान केवल खनिज संपदा तक सीमित न रहकर उद्योग, तकनीक और नवाचार का केंद्र भी बने। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के परिणाम किस रूप में सामने आते हैं और विदेशी निवेश किस पैमाने पर प्रदेश की धरती पर उतरता है। लेकिन इतना तय है कि इस पहल ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों की नजर में एक उभरता हुआ गंतव्य जरूर बना दिया है।

भाजपा MLA नरेन्द्र कुशवाहा की करतूत से धूमिल हुई भाजपा की छवि, कलेक्टर पर उठाया हाथ

(पेज 1 का शेष)

पुरानी करतूतें भी उजागर

नरेन्द्र सिंह कुशवाहा पर इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। खासकर रेत चोरी जैसे गंभीर आरोपों ने उनकी छवि को बार-बार संदेह के घेरे में डाला है। जानकारों का कहना है कि जब प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर कार्रवाई तेज की तो विधायक को अपना राजनैतिक और आर्थिक हित खतरे में नजर आया। इसी बौखलाहट में उन्होंने कलेक्टर पर रौब दिखाने की कोशिश की। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि निजी स्वार्थ के लिए विधायक प्रशासन की गरिमा तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते।

भाजपा संगठन पर उठे सवाल

यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के जनप्रतिनिधि अनुशासनहीनता और पद के घमंड में आकर मर्यादाएं तोड़ते दिखे हों। इससे पहले भी मंत्री विजय शाह, विधायक भूपेन्द्र सिंह, विधायक केपी त्रिपाठी, इंदौर विधायक गोलू शुक्ला, विधायक प्रदीप पटेल, विधायक प्रतीम लोधी, नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, देवास महापौर गीता अग्रवाल और सागर महापौर संगीता तिवारी को पद की अहमियत दिखाने और अनुशासन तोड़ने पर संगठन की ओर से हिदायतें दी जा चुकी हैं। बावजूद इसके, नेताओं का रवैया सुधरने की बजाय और बेलगाम होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आखिर कब तक महज चेतावनी देकर चुप रहेंगे। क्या भाजपा केवल भाषणों में ही अनुशासन की दुहाई देती रहेगी या फिर अपने ही नेताओं पर सख्त कार्रवाई भी करेगी?

अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों का मानना है कि विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। यदि भाजपा सचमुच सुशासन और अनुशासन को लेकर गंभीर है, तो उसे किसी भी दबाव या राजनीतिक समीकरण की परवाह किए बिना विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसा न करने पर भाजपा की साख पर स्थायी धब्बा लगना तय है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान

भारत का लोकतंत्र इस सिद्धांत पर टिका है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर विकास और सुशासन सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यदि विधायक ही प्रशासनिक प्रमुख पर हाथ उठाएंगे तो यह केवल लोकतंत्र का अपमान नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा है। कलेक्टर पर हाथ उठाना केवल एक अफसर की बेइज्जती नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का अपमान है जो जनता की सेवा के लिए दिन-रात काम करता है।

भाजपा की कसौटी पर कसता वक्त

भाजपा का दावा है कि वह अन्य दलों से अलग है और अनुशासन उसके संगठन का मूलमंत्र है। लेकिन अब समय आ गया है कि वह अपने इस दावे को साबित करे। भाजपा यदि इस घटना पर नरमी दिखाती है तो जनता का विश्वास टूटेगा और विपक्ष को पार्टी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा का कलेक्टर पर हाथ उठाना न केवल एक व्यक्तिगत दुर्व्यवहार है बल्कि पूरी पार्टी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगा गहरा धब्बा है। ऐसे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की गरिमा और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा संगठन को यह समझना होगा कि ऐसी घटनाएं उसकी साख को गहरा नुकसान पहुँचा रही हैं। यदि भाजपा सचमुच "सबका साथ, सबका विकास और सुशासन" की राजनीति पर कायम रहना चाहती है तो उसे बिना देर किए विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यह केवल प्रशासनिक गरिमा की रक्षा का मामला नहीं, बल्कि पार्टी की छवि बचाने की भी अंतिम कसौटी है।

सुशासन तिहार और विकास योजनाओं ने मुख्यमंत्री साय को दिलाया सर्वे में ऊँचा स्थान

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में उनके गृह राज्य के 41.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, जो फरवरी 2025 के 39 प्रतिशत से बढ़कर दर्ज हुआ है। यानी महज छह महीनों में मुख्यमंत्री के प्रति जनता की संतुष्टि में 2.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि बड़े राज्यों की श्रेणी में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित करती है। इंडिया टुडे–C Voter के Mood of the Nation (MOTN) Survey में यह आंकड़े सामने आये हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश भर का व्यापक भ्रमण करते हुए आमजन की समस्याओं को सीधे सुना और शिकायत निवारण समाधान शिविरों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। इस पहल से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर नई गति मिली। साथ ही निचले प्रशासनिक तंत्र की कमियाँ उजागर हुईं, जिन्हें तत्परता से दूर किया गया। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशील और सक्रिय कार्यशैली जनता को निकटता से महसूस हुई, जिससे उनके प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ। केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों का पूरा होना, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीबों, महिलाओं और किसानों के बीच भरोसे और संतोष की भावना को और गहरा किया। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा निवेश और व्यापार-व्यवसाय के नए अवसरों ने प्रदेश में नई आशा और उत्साह का संचार किया। मुख्यमंत्री की सरल, सौम्य और ईमानदार छवि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दिलाई है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सुधारों ने शासन के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत किया है और उन्हें 'बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री' के रूप में स्थापित किया है। सर्वेक्षण के परिणाम यह संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ और कार्यक्रम जनता तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं।

महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों को राहत पहुँचाने वाली कृषि योजनाएँ, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम तथा गरीब परिवारों के लिए संचालित कल्याणकारी उपायों ने जनता की संतुष्टि को मजबूती प्रदान की है। बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। सड़कों, पुलों, सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं को गति देने के साथ ही रेलवे और उद्योग आधारित ढाँचागत विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं जिलों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों को समझते हैं और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इससे आम नागरिकों को सीधे शासन से जुड़ाव का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने राज्य के किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

सरिता संदीप जैन ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी कला। देवरी नगर पालिका में लंबे समय से चले जा रहे घमासान के बाद 29 अगस्त को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव आर के कार्तिकेय द्वारा आदेश जारी करते हुए श्रीमती सरिता पति संदीप जैन को नगर पालिका के अध्यक्ष पद का प्रभार आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है। इसके बाद नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर श्रीमती सरिता संदीप जैन ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी और पार्षदों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई प्रेषित की। इस दौरान सरिता संदीप जैन ने बताया है सच्चाई की जीत हुई, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। भले ही देर कितनी लग जाए और आज आखिरकार सत्य की विजय हुई और अब देवरी का लंबे समय से रुका हुआ विकास फिर तेज गति से शुरू होगा और देवरी स्वच्छ और सुंदर देवरी बनेगी। इस दौरान उमेश पलिया, नारायण वाल्मीकि, श्रीमती सुनीता दामोदर लोधी, सुनील रिछारिया, भारतेंदु मोंटू सिंह राजपूत, काशीराम पटेल, दिलीप कोष्टी, अजीत धुर्वे उपयंत्री, मुकेश नामदेव, शंभू वाल्मीकि और देवेंद्र पलिया, मोनू भटेले सहित सभी पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। पिछले फरवरी 2024 से पीआईसी भंग होने के बाद लगातार 12 पार्षद अध्यक्ष के विरोध में लामबंद थे और विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र के विधायक बृजबिहारी पटेरिया द्वारा विधानसभा में अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर प्रश्न भी लगाया था। इसके बाद प्रशासन ने 25 अगस्त को अनियमितताओं में दोषी पाए जाने पर अध्यक्ष को पद से पृथक करते हुए, 29 अगस्त को अध्यक्ष का प्रभार श्रीमती सरिता संदीप जैन को सौंपने के लिए आदेश जारी किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। भाऊ साहेब भुस्कुटे शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन स्किल हब के सहयोग से महाविद्यालय परिसर स्थित वाल्मीकि भवन आईटी कंप्यूटर लैब में प्रातः 11:45 बजे प्रारंभ हुआ तथा गूगल मीट के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ डॉ. संजय साहू ने विद्यार्थियों को एआई की व्यावहारिक उपयोगिता एवं भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अरुण सिकरवार ने एआई को आधुनिक युग की सबसे क्रांतिकारी तकनीक बताते हुए विद्यार्थियों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. सुनील बौरासी ने रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला तथा सह-प्रभारी डॉ. दीपक मालाकार ने विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल विकसित करने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में 40 विद्यार्थी ऑफलाइन एवं 35 विद्यार्थी ऑनलाइन सम्मिलित हुए। पंजीकृत विद्यार्थियों को ई-सर्टिफिकेट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रम सफल रहा

गांव-गांव शराब का कारोबारः ठेका कंपनियों की साजिश में फंसते युवा

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के सैकड़ों गांवों में शराब की अवैध बिक्री ने ग्राम्य जीवन को खोखला करना शुरू कर दिया है। ठेका कंपनियों के एजेंट गांव-गांव पहुंचकर शराब की पेटियां थमा रहे हैं और लोक लुभावने लालच दिखाकर युवाओं से कमीशन पर यह शराब बिकवा रहे हैं। नतीजा यह है कि मोहल्लों और गलियों में ही शराब की दुकानें जैसी स्थिति बन गई है, जहां 15 साल का किशोर से लेकर 65 साल का बुजुर्ग तक नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर यही शराब केवल ठेके पर बिके तो इसका सेवन सीमित रहेगा और नशा भी समय के साथ उतर जाएगा, जिससे गांव का माहौल इतना नहीं बिगड़ेगा। लेकिन घर-घर शराब की आसान उपलब्धता ने पूरे ग्रामीण ताने-बाने को प्रभावित कर दिया है। ग्राम पंचायतें और सामाजिक संस्थाएं कई बार शराब निषेध अभियान चलाने की कोशिश कर चुकी हैं, किंतु ठोस जनभागीदारी और प्रशासनिक सख्ती के अभाव में हालात जस के तस बने हुए हैं। पुलिस भी नशा मुक्ति के आयोजन करती है, लेकिन गांव-गांव फैले इस धंधे की जानकारी शायद ही कभी सही रूप से प्रशासन तक पहुंच पाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जितनी शराब ठेके से नहीं बिकती, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में गांवों में अवैध रूप से खपाई जा रही है। युवा वर्ग खुद शराब की बिक्री और तस्करी में शामिल हो रहा है, जिससे समाज और भी गहरे संकट में फंस रहा है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक गांव की पंचायत शराब विरोधी ठोस रणनीति बनाए। महिलाओं की टोली मशालें और नारे लेकर सड़कों पर उतरे, गांव से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक अपनी आवाज बुलंद करे। क्योंकि गांव-गांव बिक रही यह शराब केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने और अगली पीढ़ी के भविष्य को भी निगल रही है। स्पष्ट है अब या तो गांव शराब मुक्त होंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियां इस नशे में डूबकर बरबादी की ओर जाएंगी।

वात्सल्य विदिशा का आदर्श स्कूल, जहॉं बच्चों को मिल रही सनातन की भी शिक्षा

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। वात्सल्य विद्यालय में आयोजित गणपति महोत्सव में केन्द्रीय कृषि-किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ, अन्य अतिथिगणों में भाजपा जिला अध्यक्ष महाराज सिंह दांगी, हरिसिंह सप्रे, राकेश जादौन, संदीप डोंगर सिंह, राकेश कटारे, सुरेन्द्र सिंह चौहान, तीरथ दरबार व अभिभावकगण उपस्थित हुए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने गणपति जी की आराधना एवं आरती की। छात्रों की प्रस्तुतियों एवं उत्सव की भव्यता को देखकर उन्होंने छात्रों को उत्साहित करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा स्वयं को कमजोर न समझे, ईश्वर ने सभी को एक-समान बुद्धि दी है, आप सभी खूब पढ़े और लिखें। पढ़ने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें क्योंकि भगवान श्री गणेश ही बुद्धि के प्रदाता है और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। इसलिए हमें अपने कोई भी कार्य करने से पहले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का ध्यान करके उस कार्य को आरंभ करना चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्गार देते हुए स्वामी विवेकानंद के दिए गए उपदेश को बताया कि उन्होंने कहा था कि हम या आप हाड़-मॉस का पुतला नहीं है बल्कि अमृत के पुत्र या पुत्री है हम सभी में ईश्वर का अंश है इसलिए हमें स्वयं को कभी-भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमारी यह सोच होनी चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली है और हर कार्य करने की क्षमता हममें है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम कर पायेंगे।

उन्होंने कहा कि वात्सल्य विदिशा का आदर्श स्कूल है जहॉं बच्चों को मिल रही सनातन संस्कृति की भी शिक्षा मिल रही है। इस तरह के भव्य आयोजन से बच्चों को पढ़ने-लिखने के साथ-साथ अपने देश की संस्कृति व सनातन धर्म को समझने व सीखने का मौका मिलता है जिससे उनका चहुमुखी विकास होता है जिससे वह शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ वातावरण में अपना विकास करते हुए सफलता पा सकते है, विदिशा में वात्सल्य विद्यालय वह आदर्श विद्यालय है जहॉं बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा मिल रही है।

सम्पादकीय

अमेरिका और भारत के बीच जारी टैरिफ वार से किसे होगा फायदा और किसे नुकसान

अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान भर नहीं है, बल्कि यह देशों के बीच राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों की मजबूती का भी प्रतीक है। जब दो बड़े लोकतांत्रिक देश- अमेरिका और भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में टकराव की स्थिति में आते हैं, तो इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य पर भी पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच टैरिफ यानी आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को लेकर विवाद गहराया है। इसे आम तौर पर "टैरिफ वार" कहा जा रहा है। सवाल यह है कि इस टकराव से असल में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान झेलना पड़ेगा। अमेरिका लंबे समय से भारत से अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश करता रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह विवाद और तीखा हो गया। अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यात उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया और साथ ही भारत को जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज) का लाभ देना बंद कर दिया, जिससे भारत को निर्यात में नुकसान हुआ। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों, बादाम, अखरोट और अन्य आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया।

निर्यात पर दबाव– अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वस्त्र, आईटी सेवाएं, दवाइयां, आभूषण और कृषि उत्पाद अमेरिका में भारी मात्रा में जाते हैं। टैरिफ बढ़ने से इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है।

जीएसपी का नुकसान– जीएसपी के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में लगभग 6 अरब डॉलर के निर्यात पर विशेष छूट मिलती थी। यह छूट समाप्त होने से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ गई।

कृषि क्षेत्र पर असर– अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाने से भारतीय मसालों, चावल और अन्य कृषि उत्पादों की मांग प्रभावित हो सकती है।

विदेशी निवेश पर दबाव– व्यापारिक तनाव से निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश को लेकर सतर्क रुख अपना सकती हैं।

अमेरिका को होने वाला नुकसान

भारतीय बाजार का महत्व– भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और लगभग 140 करोड़ की आबादी के साथ यह विशाल उपभोक्ता बाजार है। टैरिफ युद्ध से अमेरिकी कंपनियों की भारत में पैठ कमजोर हो सकती है।

कृषि उत्पादों का झटका– भारत अमेरिकी बादाम, अखरोट और दालों का बड़ा आयातक रहा है। भारत द्वारा इन पर शुल्क बढ़ाने से अमेरिकी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा।

ऊर्जा और तकनीक क्षेत्र– भारत अमेरिकी एलएनजी और हाई-टेक उत्पादों का बड़ा खरीदार है। व्यापारिक असंतुलन से इन क्षेत्रों में निर्यात घट सकता है।

रणनीतिक साझेदारी पर असर– भारत अमेरिका का एशिया में रणनीतिक साझेदार है। व्यापारिक टकराव से कूटनीतिक रिश्तों में भी खिंचाव आ सकता है, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा।

अमेरिका और भारत के बीच जारी टैरिफ वार का न तो अमेरिका को स्थायी फायदा है और न ही भारत को। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक अवसरों को सीमित करता है और आपसी भरोसे को चोट पहुंचाता है। अल्पकालिक रूप से घरेलू उद्योगों को कुछ सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं और वैश्विक साझेदारी को कमजोर करेगा। भारत और अमेरिका दोनों के लिए यही उचित होगा कि वे इस विवाद को सहयोग और संवाद के जरिए सुलझाएं, क्योंकि आज की दुनिया में आर्थिक प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है परस्पर सहयोग। टकराव से अंततः सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा, जबकि फायदा किसी तीसरे देश को मिल जाएगा।

सियासी गहमागहमी

मुख्य सचिव का एक्सटेंशन और अफसरों के सीने का सांप

सरकारी गलियारों में कभी-कभी फैसले ऐसे होते हैं, जिनसे कुर्सियाँ हिलती नहीं, बल्कि और कस जाती हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिला एक्सटेंशन भी कुछ ऐसा ही है। जहां उनके समर्थकों ने इसे "अनुभव का सम्मान" बताया, वहीं कई अफसरों के सीने में बैठे सांप ने फिर से फन उठा लिया है। दरअसल, अफसरशाही में सबसे बड़ा सपना होता है मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठना। लेकिन यह कुर्सी तो मानो हवाई जहाज की बिजनेस क्लास सीट हो। सीट लिमिटेड और चाहने वाले अनलिमिटेड। जिन अफसरों ने रिटायरमेंट कैलेंडर देखकर अपनी घड़ी मिलाई थी, उन्हें अब घड़ी बदलनी पड़ रही है। उनकी योजना थी कि "अबकी बार हमारी बारी", लेकिन बारी आई और वापस लौट गई, जैसे रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में अटकी टिकट। अब स्थिति यह है कि कई वरिष्ठ अधिकारी बधाई देते हुए भी भीतर से वही सोच रहे हैं- "भाई, बधाई तो दे रहे हैं पर हमारी बारी कब आएगी?"। एक्सटेंशन ने साबित कर दिया कि अफसरशाही में धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना सरकारी फ़ाइल को धूप दिखाना। संक्षेप में कहें तो अनुराग जैन के अनुभव ने अफसरों की उम्मीदों को फिर से 'ऑन होल्ड' पर डाल दिया है।

मुरैना विधायक-कलेक्टर प्रकरण अफसरों की आतुरता का आलम

राजनीति और अफसरशाही का रिश्ता वैसे तो "बॉस और कर्मचारी" वाला होता है, पर मुरैना में हाल ही में घटे वाकये ने इसे "बॉस बनाम बॉस" बना दिया। विधायक जी ने कलेक्टर साहब के साथ ऐसी करतूत कर दी कि अब आईएएस बिरादरी बदले की आग में तप रही है। अफसरों की हालत वैसी हो गई है जैसे किसी शेर के बच्चे को थप्पड़ पड़ जाए और पूरी शेरनी सभा खड़ी हो जाए। अब अफसरों के ग्रुप्स में चर्चा है—"ये तो लोकतंत्र का अपमान है, इसका बदला लेना ही होगा।" मानो कोई वेब सीरीज चल रही हो जिसमें अगला सीजन "बदला—आईएएस रिटन्र्स" आने वाला है। कोई कह रहा है ट्रांसफर की फाइल में विधायक जी का पसीना निकाल देंगे, तो कोई सोच रहा है अगली मीटिंग में उन्हें केवल पानी की बोतल तक सीमित कर देंगे। विधायक जी भी सोच में पड़ गए होंगे कि "थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर लेता तो आज ये आफत न आती।" आखिरकार, राजनीति में कुर्सी जनता देती है, पर अफसरशाही में फाइल अफसर ही चलाते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मेनस्ट्रीम मीडिया में बहुजन समाज की आवाजें और कहानियां नदारद हैं।
इसलिए वो अपना सच सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें हिंसा, धमकियों और झूठ्दों का सामना करना पड़ता है।

हम 90% की आवाज के साथ खड़े है, हम इसे खामोश नहीं होने देंगे।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

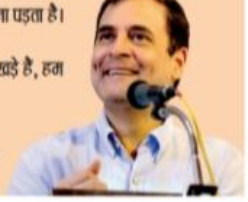

बिहार के कांग्रेस दफ्तर पर हमला करके बीजेपी ने लोकतंत्र को ललकारा है। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी।

हम असत्य और हिंसा का जवाब सत्य और अहिंसा से देते रहेंगे।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

वेंकैया नायडू दृढ़ संकल्प, सादगी और मेहनत से राजनीति में लाए सकारात्मक बदलाव

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी सादगी, स्पष्टवादिता और जनहितैषी दृष्टिकोण से जनता के दिलों में एक अलग स्थान बनाया। उन्हीं नेताओं में से एक हैं वेंकैया नायडू। वह एक प्रखर वक्ता, संगठनकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहते हुए संसद, सरकार और पार्टी संगठन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। देश के तेरहवें उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले के चावटपल्ली गांव में हुआ। वह एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं। बचपन से ही उनका रुझान सामाजिक कार्यों और ग्रामीण जीवन की समस्याओं की ओर रहा। प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली और फिर कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही वह वाद-विवाद और वक्तृत्व कला में निपुण थे। उनके भाषणों की शैली इतनी प्रभावशाली थी कि विद्यार्थी वर्ग में उनकी पहचान एक ऊर्जावान वक्ता के रूप में बनने लगी।

नायडू का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ हुआ। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े और 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान सक्रिय रहे। आपातकाल का विरोध करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी दौर में उन्होंने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता की आवाज की अहमियत को और गहराई से समझा। यह अनुभव आगे चलकर उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा तय करने वाला सिद्ध हुआ।

आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो नायडू सक्रिय रूप से उससे जुड़े। बाद में भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय से ही वे पार्टी के साथ जुड़े रहे। संगठन में उनकी मेहनत, निष्ठा और प्रखर वक्तृत्व ने उन्हें धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1998 में वह पहली बार राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद लगातार कई बार इस उच्च सदन के सदस्य चुने गए। संसद में उनकी उपस्थिति सदैव सक्रिय और सार्थक रही। वह विभिन्न समितियों और मंत्रालयों से जुड़े रहे। भाजपा संगठन में भी उन्होंने महासचिव, प्रवक्ता और अध्यक्ष जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ष 2000 से 2002 के बीच वह ग्रामीण विकास मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। शहरी विकास मंत्री के रूप में नायडू ने स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को गति दी। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करना और शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका सरकार और विपक्ष के बीच संवाद और समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही।

वर्ष 2017 में जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाया। उनका व्यक्तित्व, अनुभव और सर्वस्वीकार्य छवि देखते हुए उन्हें भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। 11 अगस्त 2017 को उन्होंने देश के तेरहवें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

उपराष्ट्रपति पद के साथ-साथ उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। राज्यसभा में उनकी कार्यशैली अनुशासन, संवाद और स्पष्टवादिता पर आधारित रही। उन्होंने सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और सारगर्भित बनाने के लिए कई सुधार किए। वेंकैया नायडू की सबसे बड़ी विशेषता उनका सरल और स्पष्ट व्यक्तित्व है। वह जमीनी राजनीति से जुड़े नेता रहे हैं, जिनका सीधा संवाद जनता से रहा। उनकी भाषण शैली में प्रायः लोकभाषा, मुहावरे और सहज हास्य का प्रयोग देखने को मिलता है, जो उन्हें जनता के और करीब ले जाता है। वह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मातृभाषा के महत्व के प्रबल समर्थक हैं। कई अवसरों पर उन्होंने अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाओं के उपयोग पर जोर दिया और युवाओं को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना रखने का संदेश दिया। वेंकैया नायडू का जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, सादगी और मेहनत से राजनीति में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। छात्र जीवन से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक का उनका सफर संघर्ष, समर्पण और सेवा भावना से भरा हुआ है। वह केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे प्रहरी और भारतीय संस्कृति के प्रखर प्रवक्ता भी हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि राजनीति केवल सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का एक माध्यम है।

कलम के सिपाही

सोमदत्त शास्त्रीः व्यवहार में सरल, सहज, आत्मीय

-अलीम बजमी

चौड़ा माथा, खिचड़ी बाल, कभी सूट तो कभी सफारी पहने नजर आते थे वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री। व्यवहार में सरल, सहज, आत्मीय। मुस्कुराता चेहरा। मुँह में पान। चश्मा कभी आँखों तो कभी माथे पर दिखाई देता। हमेशा मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते। कलम के धनी। शब्द साधक। पेशे के लिए ईमानदार। शब्दचित्र खींचने में महारत। नए विषय गढ़ने का फन। भाषा हमेशा कलात्मक। सृजनात्मक पत्रकारिता के पक्षधर। रचनात्मक पत्रकारिता के हिमायती। समाजिक सरोकार से नाता। क्राइम रिपोर्टिंग में भी खूब लोहा मनवाया। उनकी एक पहचान छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति के जानकार के रूप में भी थी। शास्त्रीजी के साथ मेरे आत्मीय रिश्ते दैनिक भास्कर में साथ काम करते हुए कायम हुए। ये लगातार बने रहे। फोन करके एक-दूसरे की खैरियत पूछना, गर्मजोशी से मिलना उनकी खासियत थीं। कई अवसरों पर मैं उन्हें कामकाजी व्यस्तता में फोन करना भूलता तो उनका फोन पलटकर आता, फिर सुनने को मिलता कहां हो राजा..? मिलते नहीं हो? मैं उनसे माफी माँगता तो फौरन कहते... अरे राजा तुम तो संजीदा हो गए। नौकरी की परेशानियों और कामकाजी झमेले को मैं भी समझता हूँ। फुर्सत में था तो खैरियत मालूम करने फोन लगा दिया। चलो बस काम करो। फिर मिलते हैं। उनकी जीवटता की ये बड़ी मिसाल थी कि शायद दो या तीन साल से किडनी के फेल होने पर भी उनके चेहरे पर इसकी शिकन नहीं थीं। हँसते, गुदगुदाते फिर ठहाका लगाते। अच्छा लिखने पर बधाई देते।

अब बात उनकी खासियत की। राजनीतिक, सामाजिक विषयों के लेखन में महारत हासिल थी। फीचर, रिपोर्ताज और इण्टरव्यू का लहजा अलहदा होता। कई बार लेखन आतिशी होता तो कई अवसरों पर मखमली। अब बात पत्रकारिता के सफर की। इब्तिदा 1975 से हुई लेकिन खबरिया जगत में पहचान ब्लिट्ज में 40 साल पहले छपी नीलू हत्याकाण्ड की रपट से मिली थी। शुरुआती दौर में वे ब्लिट्ज, करंट, दिनमान, संडे मेल, प्रॉब इंडिया, मनोहर कहानियाँ, मनोरमा, सत्यकथा के लिए कलम चलाते रहे। 1984 में बिलासपुर से प्रकाशित लोक स्वर में सहायक सम्पादक के रूप में काम किया। कुछ माह प्रजाशक्ति में भी रहे। इसके बाद रीवा जागरण के प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1990 में काम किया। वर्ष 1993 में भोपाल दैनिक जागरण ज्वाइन कर लिया। अल्प समय में अपने काम के बूते पर वे पदोन्नत होकर प्रभारी संपादक बन गए। वर्ष 2002 में न्यूज एडिटर के रूप में भोपाल दैनिक भास्कर ज्वाइन किया। भास्कर में रहते हुए उन्होंने खबरों के कंटेट पर मुख्य रूप से काम किया। हैडिंग एवं डमी बनाने की उन्हें महारात हासिल थी। वे हमेशा अपने सहयोगियों का उत्साह वर्धन करते थे। इस कारण भास्कर में अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। चुनौतियों का सामना करने में वे कभी पीछे नहीं हटते। वर्ष 2005 में भास्कर छोड़ने के बाद उन्होंने जबलपुर भास्कर ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ वर्ष रहने के बाद बहुमत के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरु किया। वहीं डिजिटल युग को देखते हुए उन्होंने वर्ल्ड ब्यूरोक्रे ट पोर्टल शुरु किया। इस पोर्टल को लेकर वे काफी उत्साहित थे।

वे जीवन के अन्तिम दिनों में सिद्धान्ता अस्पताल में दाखिल थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अपने विद्या नगर स्थित निवास पर आ गए थे। वे खुद किडनी फेल होने की जानकारी से वाकिफ थे। डॉक्टरों ने वर्ष 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। काफी कोशिशों के बाद भी उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट लड़खड़ाती सेहत के कारण नहीं हो सका।

अक्टूबर 2020 में कोरोना होने पर वे चिरायु अस्पताल में करीब 40 दिन तक दाखिल रहे। इस दौरान 25 दिन उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया लेकिन इच्छाशक्ति के धनी शास्त्रीजी स्वस्थ होकर घर लौट आए थे।

पत्रकारिता में सक्रिय हिस्सेदारी के कारण भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, माउण्ट आबू आदि में कई संगठनों ने उन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा। इसकी चमक में वे कभी मगरूर नहीं रहे। वे मित्रों और सहयोगियों के बीच ठहाका लगाकर अपने सेहतमन्द होने का हमेशा सुबूत देते। आओ राजा उनका तकिया कलाम था। इस जुमले के बहाने संजीदा और बोझिल माहौल को खत्म करने का फन उन्हें आता था। राजनेताओं और अफसरों से नजदीकी रिश्ते होने का उन्हें कभी घमण्ड नहीं रहा। अब वे नहीं है। सिर्फ यादें हैं।

देश विभाजन के दोषी कौन?

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी एक विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है। पाठ में यह भी उल्लेख है कि विभाजन के बाद कश्मीर नई समस्या के रूप में पेश आया। भारत में यह समस्या पहले कभी मौजूद नहीं थी। इसने देश की विदेश नीति के लिए चुनौती बनाए रखी। नतीजतन कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। वस्तुतः 'भारत का विभाजन गलत विचारों के कारण हुआ। भारतीय मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज से संबंधित हैं। अतएव एक साथ नहीं रह सकते।' एनसीईआरटी के विशेष पाठ में 'विभाजन के अपराधी' शीर्षक वाले खंड में कहा है कि 'अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। किंतु यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए तीन कारण जिम्मेदार थे, एक जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की। दूसरे कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इस पर अमल किया। माउंटबेटन एक बड़ी भूल के दोशी साबित हुए।'

एनसीईआरटी ने उक्त दो पार्ट छापे हैं। इनमें छठी कक्षा से आठवीं के लिए और नौवीं कक्षा से बारहवीं के लिए एक-एक पाठ हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी में पूरक पाठ हैं, नियमित पाठ्य पुस्तकों में नहीं हैं। इसलिए इनका प्रयोग परियोजनाओं, पोस्टरों और वाद-विवादों के माध्यम से किया जाना है। ये दोनों पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में दिए गए संदेश के साथ शुरू होते हैं, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साफ है, ये पाठ पूरे देश में वाद-विवाद का ऐसा हिस्सा बनें, जिससे लोग जान सकें कि वास्तव में विभाजन के अपराधी कौन हैं। केंद्र सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होती दिख रही है। दरअसल स्वतंत्रता संघर्ष के बीच महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास से कहा था कि 'अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक मैं जीता हूं, मैं कभी भी हिन्दुस्तान का बंटवारा स्वीकार नहीं करूंगा और जहां तक मेरा वश चलेगा कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं करने दूंगा।' अलबत्ता ऐसा एकाएक क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे के समर्थन में खड़े होना पड़ गया। लार्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात में ही गांधी उनके वाग्जाल की गिरफ्त में ऐसे आए कि उनकी प्राण जाए, पर वचन न जाए, की वचनबद्धता भंग हो गई। कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद के आगे घुटने टेकती चली गई। नतीजतन भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश संसद में मोहर लगा दी गई। ब्रितानी हुकूमत में औपनिवेशिक दासता झेल रहे अखंड भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र देश बनाकर पृथक-पृथक सत्ता का हस्तांतरण करने का निर्णय ले लिया। संपूर्ण सत्ता सौंपने का दिन 14 अगस्त 1947 निश्चित किया। यह दिन भी एक तरह से दोनों देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को चिढ़ाने की दृष्टि से मुकर्रर किया गया, क्योंकि इसी दिनांक को जापान मित्र देशों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ था।

अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने की दृष्टि से बंगाल विभाजन एक ऐसा षड्यंत्रकारी घटनाक्रम रहा जो भारत विभाजन की नींव डाल गया। इस बंटवारे के फलस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी उग्र जन.भावना फूटी की बंग-भंग विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। दरअसल जब गोरी पलटन ने समूचे भारत को अपनी अधीनता में ले लिया, तब क्रांतिकारी संगठनों और विद्रोहियों के साथ कठोरता बरतने के लिए 30 सितंबर 1898 को भारत की धरती पर वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पैर पड़े। कर्जन को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ले रहे क्रांतिकारियों के दमन के लिए भेजा गया था। इस संग्राम पर नियंत्रण के बाद फिरंगी इस बात को लेकर चिंतित व सतर्क थे, कि कहीं इसकी राख में दबी चिंगारी फिर न सुलग पड़े। क्योंकि अंग्रेज भली भांति जान गए थे कि 1857 का सिलसिला टूटा नहीं है। अंग्रेजों को यह भी शंका थी कि कांग्रेस इस असंतोष को पनपने के लिए खाद. पानी देने का काम कर रही है। कर्जन ने अंग्रेजी सत्ता के संरक्षक बने मुखबिरों से ज्ञात कर लिया कि इस असंतोष को सुलगाए रखने का काम बंगाल से हो रहा है। वाकई स्वतंत्रता की यह चेतना बंगाल के जनमानस में एक बेचैनी बनकर तैर रही थी। यह बेचैनी 1857 के संग्राम जैसे रूप में फूटे, इससे पहले कर्जन ने कुटिल क्रूरता के साथ 1905 में बंगाल

के दो टुकड़े कर दिए। जबकि इस बंग. भंग का विरोध हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किया था। इस बंटवारे का मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाके को बंगाल कहा गया। अर्थात जिस भूखंड पर हिंदू-मुस्लिम संयुक्त भारतीय नागरिक के रूप में रहते चले आ रहे थे, उनका मानसिक रूप से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। इय विभाजन से सांप्रदायिक भावना की एक तरह से बुनियाद डाल दी गई, वहीं दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया। यानी फिरंगी.सत्ता के विरुद्ध एकजुटता ने देशव्यापी उग्र भावना का संचार अनजाने में कर दिया। लेकिन कर्जन ने इसे कुटिल चतुराई से मुस्लिम लीग की स्थापना में बदल दिया।

यही नहीं कर्जन ने अपने वाकचातुर्य से ढाका के नवाब सलीमुल्ला को बंगाल विभाजन का समर्थन और अचानक उदय हुए स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए राजी कर लिया। सलीमुल्ला कर्जन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सक्रिय होकर कुछ नवाबों को बरगलाकर दिसबंर 1906 में मुस्लिम लीग संगठन खड़ा कर दिया। स्वदेशी आंदोलन को विफल करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने सलीमुल्ला के साथ मिलकर हिंदू-मुस्लिमों के बीच संप्रदाय के आधर पर दंगे भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। यहीं से हिंदुओं की हत्या करने और उनकी संपत्ति लूटने व हड़पने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दुर्विनार स्थिति के निर्माण होने पर ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन ने गार्जियन अखबार में लिखा, ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार के साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हैं और मुस्लिमों के कथन पर एक तरफा यकीन करते हैं।

गवर्नर जनरल और वायसराय मिंटो ने मुस्लिम पृथकतावादियों के साथ मिलकर एक नई चाल चली। इसके तहत बंग.भंग विरोध आंदोलन को देश के एक मात्र मुस्लिम-प्रांतष की खिलाफत के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। नतीजतन मुस्लिम नेता पूरी ताकत से बंटवारे के समर्थन में आ खड़े हुए। इसी समय आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मिंटो से शिमला में मिला और मुस्लिमों के लिए पृथक मतदाता सूची बनाए जाने की मांग उठा दी। मिंटो इस मंशा पूर्ति के लिए ही भारत भेजे गए थे कि मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध एक समुदाय के रूप में खड़ा किया जाए। अतएव मिंटो ने नगर पालिकाओं, जिला मंडलों और विधान परिषदों में मुस्लिमों की संख्या आबादी के अनुपात में बढ़ाने की पहल कर दी। यही नहीं मुस्लिमों को महत्व ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी के आधार पर भी रेखांकित की गई। इसी कालखंड में हिंदुओं के खिलाफ मुल्लाओं ने घृणित प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली। एक लाल पुस्तिका छापी गई। जिसमें कहा गया कि हिंदुओं ने इस्लाम के गौरव को लूटा है। उन्होंने हमारा धन और सम्मान लूटा है। स्वदेशी का जाल बिछाकर हमारी जान लेना चाहते हैं। इसलिए वो मुसलमानों एहिंदुओं के पास अपना धन मत जाने दो। हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करो। वह सबसे नीच होगा, जो उनके साथ वंदे मातरम् कहेगा। इस सब के बावजूद कांग्रेस को उच्च शिक्षित वकील जिन्ना से समन्यवादी सहयोग की उम्मीद थी। जिन्ना के नेतृत्व में शिक्षित व युवा मुस्लिम सहयोगी बने भी रहे। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के पास हिंदू-मुस्लिम एकता और सद्भावना नष्ट-भ्रष्ट करने की औजार थी। अतएव 1909 में मोर्ले. मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता सूची की मांग मंजूर कर ली गई। इस पहल ने हिंदु-मुस्लिम एकता की राह में स्थायी दरार उत्पन्न कर दी।

06 दिसंबर 1946 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा। ये लार्ड लारेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इन्हें शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू-मुस्लिमों के बीच साझा सत्ता की योजना को मूर्त रूप देना चाहा। इस संवाद में अनेक विरोधाभासी पहलू सामने आए। जिन्ना भारत के साथ रहना तो चाहते थे, लेकिन संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण गारंटी चाहते थे। जिसमें हिंदुओं के साथ बराबरी की मांग प्रमुख थी। यही वह दौर था, जिसमें ठीक दीपावली पर्व के बीच नोआखली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नरसंहार, मंदिरों का विध्वंस और आगजनी की दर्जनों घटनाएं घटी। हिंदू महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण कराकर जबरन विवाह भी रचाए गए। इन घटनाओं से गांधी को जबरदस्त सदमा पहुंचा और शांति के लिए नोआखली पहुंच गए। बहरहाल कैबिनेट मिशन की शिमला बैठक में कोई कारगर परिणाम नहीं निकला।

लॉर्ड माउंटबेटन इतना चतुर निकला कि उसने विभाजन के लिए जिन्ना, नेहरू, पटेल और यहां तक की गांधी को भी मना लिया। भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यही नहीं पंजाब और बंगाल को भी कपड़े की तरह दो टुकड़ों में चीर दिया गया,जिससे भारत हमेशा गृह कलह की आंच से सुलगता रहे। यह पाकिस्तान के अस्तित्व से भी ज्यादा खतरनाक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझ कर 652 भारतीय रियासतों की प्रभुसत्ता उन्हें वापस सौंप दी। उन्हें भारत या पाकिस्तान मिल जाने की छूट तो थी ही, स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की छूट भी दे दी गई थी। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ विभाजन तो आधा सच है, पूरा सच तो देश के 652 टुकड़े कर देने का बन गया था। जिसे पटेल ने संभाला और रियसतों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो पाया। अतएव जिन दो पाठों में जिन्ना, कांग्रेस और लाउंटबेटन को दोशी ठहराया गया है, वह कोई केंद्र की वर्तमान सरकार का झूठ नहीं, अपितु ऐतिहासिक सत्य है, जो निश्पक्ष भाव से लिखे स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास पुस्तकों में पूर्व से ही दर्ज है।

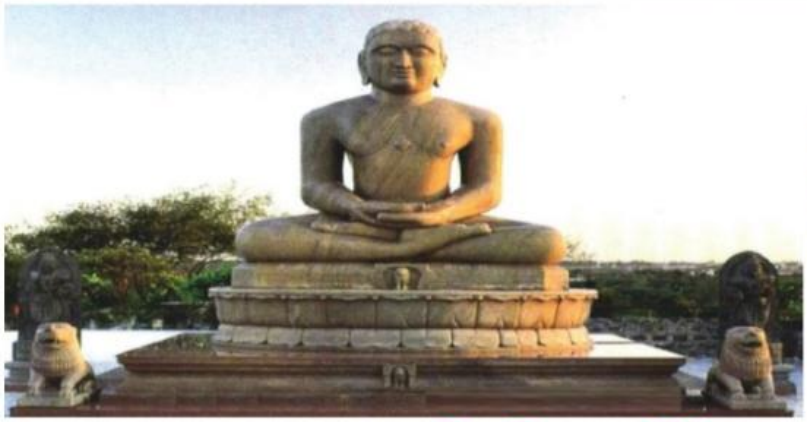

क्षमा: कमजोरी नहीं, बड़प्पन की निशानी है

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

"कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना तो ताकतवर की निशानी है।" यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का वह शक्तिशाली सूत्र है जो हमें साधारण से असाधारण बनाता है। क्षमा वह दिव्य शक्ति है जो टूटे हुए धागों को सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। जैन समाज में पर्युषण के दौरान मनाया जाने वाला क्षमा पर्व संपूर्ण मानवता के लिये एक संदेश है कि मन का बोझ उतार फेंको, क्षमा मांगो-क्षमा करो और आगे बढ़ो। चलो मिलकर मैं को नहीं हम को जिताएं। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं, तो हमारा हृदय अहंकार के बोझ से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। और जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उसे नहीं, बल्कि स्वयं को घृणा के अंधकार से निकालकर प्रेम के प्रकाश में लाते हैं। यह केवल एक धार्मिक औपचारिकता नहीं, बल्कि स्वयं को अतीत की बेड़ियों से आजाद करने का सबसे बड़ा उत्सव है।

परस्परोपग्रहो जीवानाम्

जैन धर्म और क्षमा का अमर संदेश

जैन धर्म का कण-कण 'अहिंसा परमो धर्मः' के सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल शारीरिक हिंसा की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक हिंसा, क्रोध, घृणा और द्वेष को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। शस्त्रों से पाई गई विजय अस्थायी होती है और अपने पीछे नफरत की खाई छोड़ जाती है। लेकिन क्षमा वह अस्त्र है जो शत्रुता को जड़ से समाप्त कर प्रेम के बीज अंकुरित करती है।

भगवान महावीर स्वामी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है:

"स्वयं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी विजय है।" और क्षमा करना अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पाने का सबसे सुंदर मार्ग है।

आत्मा के शुद्धिकरण का महापर्व

यह केवल एक त्योहार नहीं, यह आत्मा के मैल को धोकर उसे फिर से पवित्र बनाने का एक वार्षिक महायज्ञ है।

श्वेतांबर जैन समाजः पर्युषण पर्व आत्म-चिंतन और तपस्या का स्वर्णिम अवसर है। इसका शिखर "संवत्सरी" का दिन है, जब "मिच्छामी-दुक्कड़म" का दिव्य मंत्र हर दिशा में गूँजता है और दिलों को एक कर देता है। जो गत दिनों पूर्ण हुआ है।

दिगंबर जैन समाजः दशलक्षण पर्व (28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक) धर्म के दस लक्षणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। इसका समापन 8 सितंबर 2025 को "क्षमावाणी" दिवस के रूप में होता है, जो हमें याद दिलाता है कि समस्त धर्मों का अंतिम सार क्षमा ही है।

क्षमा पर्वः एक संदेश पूरी मानवता के लिए भले ही इस पर्व की जड़ें जैन धर्म में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं पूरी मानवता को शीतल छाया देती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि: गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना एक चुनाव है। क्षमा हमें सही चुनाव करने की आंतरिक शक्ति देती है। रिश्ते कांच के नहीं होते कि टूट जाएं, वे तो प्रेम और विश्वास की मिट्टी से बने होते हैं, जिन्हें क्षमा के जल से बार-बार संवारा जा सकता है। 'सॉरी' (Sorry) कहना एक शब्द हो सकता है, लेकिन "मिच्छामी-दुक्कड़म" कहना आत्मा की स्वीकृति है कि 'मेरे मन, वचन या कर्म से हुई किसी भी भूल के लिए मुझे क्षमा करें।' यह भाव हमें विनम्र और महान बनाता है।

आज ही करें एक नई शुरुआत

तो आइए, इस क्षमा पर्व को केवल एक परंपरा न समझकर, इसे अपने जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर बनाएं। आज ही उस फोन को उठाएं, जिससे आप बात करने में हिचक रहे हैं। आज ही उस व्यक्ति को हृदय से माफ करें, जिसकी वजह से आपको पीड़ा हुई थी। अपने मन के बोझ को उतार फेंकें और असीम शांति को अपनाएं। क्योंकि क्षमा करके आप किसी और को उपहार नहीं देते, आप स्वयं को शांति और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। चलिए, इस पर्व को सार्थक बनाएं और प्रेम, सद्भाव और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की एक नई शुरुआत करें।

धराली आपदा से सबक लें

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

अगर 2013 के केदारनाथ आपदा से कोई सबक सीखा होता तो 2021 को सीमान्त चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में धौली गंगा और ऋषिगंगा की बाढ़ की तबाही नहीं होती और न होती उत्तरकाशी के धराली की त्रासदी। यह आपदाएं हमें दिखाती हैं कि हमें पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की कितनी जरूरत है। नदी के आसपास किसी भी तरह का निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए। साल दर साल बादल फटना, भूस्खलन, पहाड़ों का दरकना एवं धंसना, ग्लेशियर का टूटना जैसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं अब डरा रही है। लेकिन लोग इसके लिए प्रकृति को दोष देते हैं। पहले भी खीर गंगा में भीषण बाढ़ आ चुकी है। इतिहास टटोलें तो खीर गंगा में भीषण बाढ़ 1835 में आई थी। तब नदी ने सारे धराली कस्बे को पाट दिया था। बाढ़ से यहां भारी मात्रा में मलबा (गाद) जमा हो गया था। कहते हैं कि यहां जो भी बसावट है, वह उस समय नदी के साथ आई गाद पर स्थित है। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद लगा था कि राज्य सरकार और प्रशासन ने सबक लिया है, और अब नदी नाले और इनके किनारे मानवीय हस्तक्षेप से बचे रहेंगे लेकिन दुखद बात है कि गंगा के किनारों का हाल 2013 का हाल 2013 से भी बुरा हो गया है। पहाड़ों पर मान्यता है कि नदी अपने खोए हुए रास्ते पर वापस जरूर आती है। धराली में नदी के प्रचंड वेग और उसके साथ बड़ी बड़ी इमारतों, होटलों, घरों के बहने का दृश्य भयावह था, लेकिन इसके लिए नदी बिलकुल दोषी नहीं है। पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं कोई नई बात नहीं है, ना ही इन्हें पूरी तरह रोक जा सकता है, लेकिन उनकी तीव्रता में बढ़ोतरी स्वाभाविक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। देखा जाए तो वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण भी हिमालयी क्षेत्र के मौसम में आसमानय परिवर्तन दिख रहे हैं। वर्षा का पैटर्न असंतुलित हो गया है। बादल फटना जो कभी कभार होता था अब उसकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। प्रदेश में विगत दशकों में अनियंत्रित और अनियोजित विकास ने परेशानी बढ़ाई है। केदारनाथ आपदा, नाचनी गांव आपदा, रेनी गांव आपदा, जोशीमठ का धंसना और अब धराली की आपदा एक भयावह संकेत दे रही है कि कुछ दशकों के बाद उत्तराखंड में कई रूपखंड (जहां आज भी नरकंकाल बिखरे हुए हैं) होंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के नाम पर जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, वह यहां के पहाड़ों के मिजाज के अनुरूप नहीं है। सरकार यहां यहां आने वालों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है लेकिन यहां अनियंत्रित आवाजाही को रोकना जरूरी है। पर्यटकों की हर साल बढ़ती संख्या यहां के बुनियादी ढांचे पर दबाव पैदा कर रही है। नदी किनारे बसावट और अवैज्ञानिक निर्माण ने भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा जैसी बड़ी नदियों से लेकर छोटी बरसाती नदियों तक किनारों को होटलों, होमस्टे और बाजारों से ढक दिया है। यह निर्माण आर्थिक दृष्टि से भले लाभदायक लगे लेकिन ये आपदा प्रबन्धन के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। बाढ़, भूस्खलन या मलबे की घटना इन्हें पूरी तरह नष्ट कर देती है, जैसा धराली में देखने को मिला। इस परिपेक्ष्य में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार, प्रशासन और लोगों ने इन संकेतों से कुछ सीखा है ? हर त्रासदी के बाद राहत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ तो होती है लेकिन दीर्घकालीक समाधान और नीतिगत परिवर्तन नदारद रहते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि आपदाएं कुछ ठेकेदारों और परियोजना संचालकों के लिए लाभ का माध्यम बन जाती है। इन सभी घटनाओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियां हैं। अग्रिम चेतावानी, स्थानीय प्रशिक्षण, सुरक्षित स्थानों की पहचान जैसी बुनियादी प्रावधान अब भी अधूरे और अपर्याप्त दिख रहें हैं। हमें सबक लेना चाहिए कि हिमालयी राज्यों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की स्पष्ट नीति बने। नदी के किनारे निर्माण पर सख्त प्रतिबंध हो, सड़क निर्माण से पहले भूवैज्ञानिक सर्वे के निष्कर्षों को स्वीकार किया जाए और बड़े प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभावों को गंभीरता से लिया जाए। अन्यथा पहाड़ों पर जीवन मुश्किल हो जाएगा।

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

31 लाख परिवारों को मिल रहा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

15 लाख BPL परिवारों को 30 यूनिट फ्री + हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

डबल सब्सिडी केंद्र के साथ मिल रही राज्य की भी सब्सिडी

हर महीने 200-360 यूनिट तक बिजली उत्पादन

बिजली बिल होगा शून्य बची बिजली से होगी कमाई

उपभोक्ता से बनें ऊर्जादाता

R.O. No. : 13388/ 1

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना

मासिक बिजली बिल से भी कम ई.एम.आई. में लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट

सोलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹167
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹333
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹800

*बैंक द्वारा 6% ब्याज दर पर आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध

हमारा संकल्प
हाफ बिजली से मुफ्त बिजली

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

https://pmsuryaghar.gov.in/

QR कोड स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक। RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)